गोमतीनागम पिल्लै एवं अन्य

बनाम

पलानीस्वामी नादर

2 सितंबर, 1966.

[के. एन. वांचू, जे. सी. शाह और आर. एस. बचावत, जे. जे.]

संविदा, अधिनियम, 1872, धारा, 55-समय को अनुबंध का सार समझना विशिष्ट पालना - यदि डिक्री तब तक दी जा सकती है जब तक कि दावा करने वाला पक्ष यह नहीं दिखा सके कि वह अपनी भूमिका निभाने के लिए हर समय तैयार और तत्पर था।

जी और उनके बेटे सी, पहले और दूसरे अपीलकर्ता थे, एक भूखंड के मालिक जिसे वे बेचने के लिए मौखिक रूप से सहमत हुए थे, 5 मार्च 1959 को प्रतिवादी को, उस समय जब पी, जी का एक और बेटा, हत्या के मुकदमे में विचाराधीन था अपनी रक्षा के लिए तत्काल धन की आवश्यकता थी। उस तिथि को, जैसे रुपये की कुल तय कीमत के लिए 15,106 प्रतिवादी उन्हें रुपये का भुगतान किया जाना था, लेकिन अग्रिम राशि के रूप में 1006 रूपये अदा कर उसकी रसीद दो अपीलकर्ताओं द्वारा निष्पादित किया गया था। विक्रय के लिए लिए कोई समय निर्धारित नहीं था। 4 अप्रैल 1959 को 2000 रूपये की प्राप्ति दोनों ने बिक्री विलेख निर्धारित करते हुए एक लेख निष्पादित किया 15 अप्रैल, 1959 को या

उससे पहले विक्रय विलेख निष्पादित किया जाएगा। इस लेखन में जुर्माना लगाने के लिए एक डिफॉल्ट क्लॉज भी शामिल किया गया। पार्टी सहमत तिथि तक बिक्री पूरी करने में विफल रही। हालाँकि, विक्रय विलेख उस तिथि तक निष्पादित नहीं किया गया था प्रत्येक पक्ष द्वारा अलग-अलग कारण बताए गए। 15 अप्रैल को, एक और समझौता निष्पादित किया गया जिसके तहत 30 अप्रैल 1959 तक बिक्री पूरी करने पर सहमति हुई। लेकिन यह उस तिथि तक भी पूरा नहीं हुआ। 30 जुलाई 1959 को अपीलकर्ताओं 1 और 2 ने प्रतिवादी को लिखा प्रतिवादी समझौता एक विशेष शर्त के अधीन था कि उस समय समझौते का सार था और चूंकि प्रतिवादी इसे 30 अप्रैल 1959 तक पूरा करने में विफल रहा था। अतः समझौता रद्द कर दिया गया और अग्रिम राशि जब्त कर ली गई। इसके बाद 9 जुलाई, 1959 को अपीलकर्ता 1 और 2 बेचने पर सहमत हुए तीसरे अपीलकर्ता को भूमि। 3 अगस्त 1959 को प्रतिवादी ने देय राशि की शेष राशि बैंक में जमा कर दी और अपीलकर्ताओं को सूचित किया कि वह तैयार है और अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के इच्छुक हैं और अपीलकर्ताओं 1 और 2 को विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए तीन दिन के भीतर बुलाया गया। अपीलकर्ता विक्रय विलेख निष्पादित करने में विफल रहे प्रतिवादी ने उनके विरुद्ध वर्तमान मुकदमा संस्थित किया। समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री।

उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को पलट दिया, और विशिष्ट पालना के लिए प्रतिवादी के दावे पर फैसला सुनाया

इस न्यायालय में अपील पर,

अभिनिर्धारित- (वांचू और शाह, जे.जे., द्वारा बाचावत, जे. द्वारा डिसेंटिंग) हालाँकि उच्च न्यायालय ने सही ठहराया था कि समय अनुबंध का सार नहीं था, ट्रायल कोर्ट का निर्णय कि प्रतिवादी अनुबंध में प्रवेश करने के बाद अपना काम करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, स्वीकार किया जाना चाहिए; विशिष्ट पालना के लिए डिक्री इसलिए प्रदान नहीं की जा सकती।

4 अप्रैल और 15 अप्रैल के समझौतों में व्यक्त नहीं किया गया समय संविदा का सार और होना था व डिफ़ॉल्ट कलोज यह मंश सिद्ध नहीं कर सकता। अवधि का निर्धारण जिसके भीतर अनुबंध निष्पादित किया जाना है, वह समय को अनुबंध का सार नहीं बनाता है। यदि उसे सार बनाना है तो या तो शर्तों को व्यक्त करें या ऐसी परिस्थितियाँ हो जो सामान्य रूप से पर्याप्त हो सिद्ध करने के लिए की भूमि की बिक्री के अनुबंध में समय सार के नहीं हैं। वर्तमान मामले में स्पष्ट शर्त, और परिस्थितियाँ ऐसी नहीं थीं यह इंगित करने के लिए कि पार्टियों का इरादा था समय को अनुबंध का सार बनाने का। [233 ई-एच; 238 ईएफ]

इससे पहले कि उसे विशिष्ट पालना के लिए डिक्री प्रदान की जा सके प्रतिवादी को अपनी तत्परता साबित करनी थी, अनुबंध की तारीख से लगातार मुकदमे की सुनवाई की तारीख तक और यदि वह उसमें विफल रहता है, तो उसका मुकदमा असफल होगा। ट्रायल कोर्ट ने सबूतों के आधार पर पाया था कि प्रतिवादी किसी भी समय अपना कार्य करने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं था। इसे उच्च न्यायालय में कभी चुनौती नहीं दी गई और उच्च न्यायालय ने उस पर विचार नहीं किया कि निष्कर्ष गलत था. [234 सी]

(बच्चावत जे. की असहमति): इस प्रश्न पर कोई विवाद नहीं था कि क्या प्रतिवादी तैयार और इच्छुक था अनुबंध निष्पादित करने के लिए। ट्रायल कोर्ट स्पष्ट रूप से गलत था यह निष्कर्ष निकालते हुए कि प्रतिवादी तैयार और इच्छुक नहीं था। इस तथ्य से कि अनुबंध निष्पादित करने के लिए कि 30 अप्रैल से, 1959 जुलाई 1959 के मध्य तक प्रतिवादी द्वारा कोई कदम नहीं उठाया गया और इसकी विफलता से देरी स्पष्ट स्पष्ट नहीं हुई। यदि प्रतिवादी विलंब का दोषी था तो उचित समय तय करना अपीलकर्ताओं का कर्तव्य था। महज़ देरी, जो वेवर की श्रेणी में ना आती हो, वह अनुतोष प्रदान करने के लिए इनकार करने का कोई आधार नहीं है, न ही यह तत्परता की कमी का सबूत है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट

रूप से इंगित करती है कि 'प्रतिवादी हर समय तैयार था और अनुबंध का पालन करने को इच्छुक था [239 ई; 241 डीएफ]

सिविल, अपीलीय क्षेत्राधिकार: 1965 की सिविल अपील संख्या 1043।

1961 के अपील वाद संख्या 375 में मद्रास उच्च न्यायालय के 17 दिसंबर 1964 के निर्णय और आदेश से विशेष अनुमति द्वारा अपील।

अपीलकर्ताओं की ओर से एचआर गोखले और आर. गणपति अय्यर।

प्रतिवादी की ओर से ए.के. सेन और आर. गोपालकृष्णन।

वांचू और शाह, जे जे का निर्णय। शाह द्वारा दिया गया था, जे. बच्चावत, जे. ने असहमतिपूर्ण राय दी।

शाह, जे. विशेष अनुमति के साथ यह अपील 1959 के मूल वाद संख्या 30 में अधीनस्थ न्यायाधीश, रामनाथपुरम के फैसले को अपास्त करने वाले मद्रास उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ दायर की गई है। गोमथिनायगम पिल्लई और उनके बेटे चिन्नाथंबिया हिलई-इसके बाद सामूहिक रूप से अपीलकर्ताओं के रूप में संदर्भित 1 और 2 - रामनाथपुरम जिले के पेरियाकुलम गांव में भूमि सर्वेक्षण संख्या 1155/2-3 के एक भूखंड के मालिक थे। मार्च 1959 में, पहले अपीलकर्ता के बेटे पलानीअप्पा पिल्लई पर हत्या के अपराध के लिए एक आपराधिक अदालत में मुकदमा चल रहा था और पहले अपीलकर्ता को अपने बचाव के लिए धन की

आवश्यकता थी। 5 मार्च, 1959 को अपीलकर्ता 1 और 2 ने मौखिक रूप से क्रमांक 1155/2-3 को इस अपील के प्रतिवादी पलानीस्वामी नादर 15106/- को रुपये में बेचने पर सहमति व्यक्त की और कीमत का आंशिक भुगतान 1006/- रु. प्राप्त किए। बिक्री पूरी होने का कोई समय तय नहीं किया गया था। एक रसीद एक्स ए-1 को अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा यह कहते हुए निष्पादित किया गया था कि भूमि अपीलकर्ता 1 और 2 द्वारा प्रतिवादी को बेचने के लिए सहमत हुई थी और रु. 1006/- "अग्रिम राशि" के रूप में प्राप्त हुए। 31 मार्च, 1959 को पलानीअप्पा पिल्लई को हत्या के अपराध का दोषी ठहराया गया और आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। 4 अप्रैल, 1959 को अपीलकर्ताओं 1 और 2 ने प्रतिवादी से 2,000/- रु. लिए और एक लिखित शर्त लगाई कि बिक्री विलेख 15 अप्रैल, 1959 को या उससे पहले निष्पादित किया जाएगा। उस लेखन में यह कहा गया था कि अपीलकर्ता 1 और 2 ने 5 मार्च, 1959 को बेचने के लिए सहमति व्यक्त की थी और उसी दिन 1006/- रुपये प्राप्त किए थे व 2,000/- 4 अप्रैल, 1959 को प्राप्त किए और यह लिखा गया कि अपीलकर्ता 1 और 2 चित्तिराल, विखरी (15 अप्रैल 1959) के भीतर "प्रतिवादी" के पक्ष में उपरोक्त बिक्री का निष्पादन करेंगे यदि राशि का भुगतान किया जाएगा। यदि प्रतिवादी बिक्री को निपटाने के लिए कोई आपत्ति उठाता है, तो वह 3006 रुपये की अग्रिम राशि खो देगा। (केवल तीन हजार छह रुपये); और यह कि, भले ही 'प्रतिवादी' बिक्री का निष्पादन करने के लिए तैयार है,

यदि 'अपीलकर्ता 1 और 2' बिक्री को निपटाने के लिए कोई भी आपत्ति उठाते हैं, तो उन्हें 3000/- रुपये की राशि जोड़नी होगी जो कि पूर्वोक्त अग्रिम राशि में से 306/- में होगी और कुल मिलाकर 6006/- रुपये (छह हजार छह रुपये मात्र) प्रतिवादी को अदा करें। समझौते में स्पष्ट रूप से अनुबंध की शर्तों को पूरा करने में विफल रहने वाली पार्टी पर जुर्माना लगाने का एक डिफ़ॉल्ट खंड शामिल था। लेकिन बिक्री विलेख 15 अप्रैल, 1959 को या उससे पहले निष्पादित नहीं किया गया था। निर्धारित तिथि तक बिक्री पूरी न करने के लिए पार्टियों द्वारा अलग-अलग कारण दिए गए थे। यह प्रतिवादी का मामला था कि अपीलकर्ता 1 और 2 एक वकील से परामर्श करना चाहते थे और यह सुनिश्चित करना चाहते थे कि क्या पहले अपीलकर्ता के बेटे पलानीअप्पा और उनकी बेटियों द्वारा सत्यापन करना आवश्यक था क्योंकि संपत्ति मूल रूप से पहले अपीलकर्ता की पत्नी उलगम्मल की थी। यह अपीलकर्ताओं 1 और 2 का मामला था कि वे बेचने के लिए सहमत भूमि के पूर्ण मालिक थे और पहले अपीलकर्ता के बच्चों को भूमि में कोई दिलचस्पी नहीं थी और प्रतिवादी ने झूठे बहाने बनाए और बिक्री विलेख लेने में लापरवाही की। 15 अप्रैल 1959 को एक और समझौता संपन्न हुआ। समझौते में यह कहा गया:

> "जैसा कि हम तीन व्यक्तियों द्वारा 4 अप्रैल 1959 को निष्पादित समझौते के अनुसार तय किया गया था, इस

दिन बिक्री का निपटान करने के लिए कुछ अप्रत्याशित परिस्थितियाँ उत्पन्न हो गई हैं, हमने वकील से परामर्श करने का निर्णय लिया है ताकि 30 अप्रैल 1959 के भीतर बिक्री का निपटान किया जा सके और जो कोई भी बिक्री को अंतिम रूप देने में विफल रहता है, उसे पिछले समझौते में उल्लिखित शर्तों के अनुसार खुद को बाध्य करना होगा।"

30 अप्रैल, 1959 को भी बिक्री पूरी नहीं हुई। 30 जुलाई 1959 को, अपीलकर्ता 1 और 2 ने प्रतिवादी को एक पत्र संबोधित किया जिसमें कहा गया था कि बिक्री का समझौता एक "विशिष्ट उपक्रम" के अधीन था, कि समय समझौते का सार था और इसे प्रतिवादी के अनुरोध पर दो बार बढ़ाया गया था, और चूंकि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 तक भी समझौते को पूरा करने में विफल रहा, इसलिए समझौता रद्द कर दिया गया और प्रतिवादी द्वारा भुगतान की गई 3006/- की राशि जब्त कर ली गई। 31 जुलाई, 1959 को अपीलकर्ता पीके बनारुसामी नायडू को जमीन बेचने पर सहमत हुए - जिन्हें इसके बाद अपीलकर्ता संख्या 3 के रूप में संदर्भित किया जाएगा। 3 अगस्त, 1959 को प्रतिवादी ने बिक्री के समझौते के तहत अपने द्वारा देय शेष राशि एक बैंक में जमा कर दी। , और 4 अगस्त 1959 को पत्र द्वारा अपीलकर्ताओं 1 और 2 को सूचित किया कि समय का कोई महत्व नहीं है, और वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के

लिए तैयार और इच्छुक था, और मूल्य की शेष राशि के भुगतान के विरुद्ध पत्र की प्राप्ति के तीन दिनों के भीतर बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं 1 और 2 को बुलाया। उन्होंने स्टांप पेपर खरीदने और निष्पादन के लिए विक्रय पत्र तैयार करने की भी पेशकश की।

अपीलकर्ता 1 और 2 विक्रय-पत्र को निष्पादित करने में विफल रहे, प्रतिवादी ने अपीलकर्ता 1, 2 और 3 और एक सेथुरामलिंगम पिल्लई (जिसे इस आधार पर कि वह समझौते के विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री के लिए 15 सितंबर, 1952 को 6000/- रुपये में निष्पादित विलेख द्वारा संपत्ति का गिरवीदार था, दावे में जोड़ा गया) के खिलाफ, अधीनस्थ न्यायाधीश, रामनाथपुरम की अदालत में 1959 का मूल मुकदमा संख्या 30 दायर किया। यह आरोप लगाते हुए कि वह अपने हिस्से का निष्पादन करने के लिए हर समय तैयार और इच्छुक था। यह केवल अपीलकर्ता 1 और 2 के अनुरोध पर था कि बिक्री विलेख का निष्पादन दो बार स्थगित किया गया था और अपीलकर्ता 1 और 2 ने अनुबंध का उल्लंघन किया था। मुकदमे का अपीलकर्ताओं 1, 2 और 3 द्वारा विरोध किया गया था। विद्वान ट्रायल न्यायाधीश ने यह कहते हुए मुकदमा खारिज कर दिया कि 4 अप्रैल, 1959 और 15 अप्रैल, 1959 के समझौतों के तहत समय अनुबंध का सार था, और यदि इसे अन्यथा माना भी जाए तो प्रतिवादी "अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए वह कभी भी तैयार और इच्छुक नहीं

था", कि उसने सौदेबाजी के अपने हिस्से को पूरा करने में चूक की थी, बिक्री के समझौते के तहत अपने अधिकारों का दावा करने में प्रतिवादी की ओर से देरी के कारण उसके हित में गड़बड़ी हुई थी जिस पर तीसरे अपीलकर्ता ने हस्तक्षेप किया और इस कारण प्रतिवादी को समझौते को लागू करने से रोक दिया गया, और यह देरी अनुबंध के परित्याग या अनुबंध को लागू करने के अधिकार के वेवर का सबूत थी। ट्रायल जज ने तदनुसार विशिष्ट पालना के लिए प्रतिवादी के दावे को खारिज कर दिया, लेकिन फैसला सुनाया अपीलकर्ताओं 1 और 2 द्वारा 3006/- रूपये 6 प्रतिशत ब्याज के साथ रुपये की वसूली की जा सकेगी। डिक्री की तारीख से अपीलकर्ताओं 1 और 2 के खिलाफ वसूली तक। डिक्री के खिलाफ, प्रतिवादी ने मद्रास उच्च न्यायालय में अपील की। उच्च न्यायालय ने कहा कि समय अनुबंध का सार नहीं था, 30 अप्रैल, 1959 और 30 जुलाई, 1959 के बीच बिक्री के पूरा होने का दावा करने में प्रतिवादी की ओर से देरी अनुचित देरी नहीं थी और न ही अनुबंध का परित्याग हुआ था। न ही वेवर, और यह कि "एक चूककर्ता पक्ष के रूप में भी", जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया, प्रतिवादी बिक्री के समझौते के विशिष्ट पालना के लिए डिक्री का हकदार था। तदनुसार, उच्च न्यायालय ने ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को उलट दिया, और विशिष्ट पालना के लिए प्रतिवादी के दावे पर फैसला सुनाया।

विशेष अनुमति के साथ इस अपील में, दो प्रश्न निर्धारित किए जाने हैं: (1) क्या बिक्री के समझौते के तहत, समय अनुबंध का सार था; और (2) जैसा कि अपीलकर्ताओं, 1, 2 और 3 द्वारा आरोप लगाया गया है, प्रतिवादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, और उस कारण से वह विशिष्ट प्रदर्शन के लिए डिक्री का हकदार नहीं था।

पहले प्रश्न पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालने वाले तथ्य पहले ही बताए जा चुके हैं। अनुबंध अधिनियम की धारा 55 जो पहले पैराग्राफ में निर्धारित समय पर या उससे पहले एक निष्पादन अनुबंध को पूरा करने में विफलता के परिणामों से संबंधित है:

> "जब किसी अनुबंध का कोई पक्ष किसी निश्चित समय पर या उससे पहले एक निश्चित कार्य करने का वादा करता है, या निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले कुछ कार्य करने का वादा करता है, और निर्दिष्ट समय पर या उससे पहले ऐसा कोई भी कार्य करने में विफल रहता है, तो अनुबंध, या वह जिसे पूरा नहीं किया गया है, वादा करने वाले के विकल्प पर शून्यकरणीय हो जाता है यदि पार्टियों का इरादा यह था कि समय अनुबंध का सार होना चाहिए।"

यह केवल उस समय के विनिर्देशन के कारण नहीं है जब या उससे पहले अनुबंध के तहत किए जाने वाले कार्य को पूरा करने का वादा किया जाता है और उसके अनुपालन में चूक के कारण, दूसरा पक्ष अनुबंध से बच सकता है। ऐसा विकल्प तब ही उत्पन्न होता है जब पार्टियों का यह इरादा हो कि समय अनुबंध का सार है। समय को सार बनाने का इरादा, यदि लिखित रूप में व्यक्त किया गया है, तो ऐसी भाषा में होना चाहिए जो असंदिग्ध हो जिसे संपत्ति की प्रकृति, पार्टियों के आचरण और अनुबंध पर या उससे पहले आसपास की परिस्थितियों से भी अनुमान लगाया जा सकता है। किसी अनुबंध का विशिष्ट निष्पादन आम तौर पर दिया जाएगा, तब भी जब निर्दिष्ट अवधि के भीतर अनुबंध को पूरा करने में चूक हो यदि पार्टियों की स्पष्ट शर्तों, संपत्ति की प्रकृति और आसपास की परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, राहत देना असमान नहीं है। यदि अनुबंध अचल संपत्ति की बिक्री से संबंधित है, तो आमतौर पर यह माना जाएगा कि समय अनुबंध का सार नहीं था। डिफ़ॉल्ट के मामले में जुर्माना लगाने वाले खंड के लिखित समझौते में शामिल होने मात्र से ही समय को सार बनाने का इरादा नहीं हो जाता है। जमशेद खोदाराम ईरानी बनाम बुर्जोरजी धुनजीभाई (1) में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति ने देखा कि अंतर्निहित सिद्धांत अनुबंध अधिनियम की धारा 55 भूमि की बिक्री के अनुबंधों के संबंध में इंग्लैंड के कानून के तहत प्राप्त अनुबंधों से भिन्न नहीं थी।न्यायिक समिति ने कहा:

"उस कानून के तहत इक्विटी, जो अचल संपत्ति बेचने के लिए अनुबंधों के विशिष्ट प्रदर्शन के मामलों में पार्टियों के अधिकारों को नियंत्रित करती है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि क्या पार्टियां, इसके बावजूद कि उन्होंने एक समय दिया है, शब्दों को नहीं बल्कि समझौते के सार को देखती है। जिसमें विशिष्ट समय के भीतर पूरा होना था, वास्तव में और सार रूप में इरादा था कि यह उचित समय के भीतर होना चाहिए था। इसे टिली बनाम थॉमस (1867) एलआर 3 अध्याय 61 में लॉर्ड केर्न्स द्वारा इस्तेमाल की गई भाषा में संक्षेप में कहा जा सकता है "निर्माण, न्यायलय के समान ही है, और होना ही चाहिए।" इक्विटी कोर्ट वास्तव में अनुबंध द्वारा निर्दिष्ट तिथियों को पूरा करने के लिए, या पूरा होने की दिशा में कदम उठाने में विफलता के बावजूद, विशिष्ट पालना की राहत देगा, यदि वह पार्टियों के बीच न्याय कर सकता है, और यदि (जैसा कि लॉर्ड जस्टिस टर्नर ने रॉबर्ट्स बनाम बेरी (1853) 3 डी जीएम एंड जी 284) में कहा था, 'पार्टियों के बीच स्पष्ट शर्तों, संपत्ति की प्रकृति, या आसपास की परिस्थितियों' में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो इसे कानूनी अधिकार में हस्तक्षेप करना और संशोधन करना अनुचित बनाएगा। जब यह कहा जाता है कि

इक्विटी में समय अनुबंध का सार नहीं है, तो यही अभिप्राय है। लॉर्ड जस्टिस टर्नर द्वारा उल्लिखित तीन आधारों की स्पष्ट शर्तों पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नहीं है। 'संपत्ति की प्रकृति' को प्रत्यावर्तन, खदानों या व्यापारों के मामले से दर्शाया गया है। 'आसपास की परिस्थितियाँ' प्रत्येक विशेष मामले के तथ्यों पर निर्भर होनी चाहिए।"

उनका आधिपत्य इन टिप्पणियों को अभी उद्धृत कथन में जोड़ देगा। इक्विटी के विशेष अधिकार क्षेत्र में यह सुनिश्चित करने के लिए अनुबंध के शब्दों की उपेक्षा की जाती है कि अनुबंध के किन पक्षों को वास्तव में और इसके निष्पादन के समय के संबंध में आशयित आशय में किसी भी स्पष्ट रूप से व्यक्त शर्त को बाहर रखा जा सकता है। लेकिन इस प्रभाव को प्राप्त करने के लिए शर्त की भाषा को यह दिखाना होगा कि इरादा पार्टियों के अधिकारों को निर्धारित समय सीमा के पालन पर निर्भर करने का था जो कि असंदिग्ध हो। भाषा का यह प्रभाव होगा यदि यह स्पष्ट रूप से इस धारणा को बाहर कर देती है कि ये समय सीमाएं अनुबंध में केवल द्वितीयक महत्व की थीं, और उनकी उपेक्षा करना इसकी नींव के रूप में रखी गई किसी भी चीज़ की उपेक्षा करना होगा। "प्रथम दृष्टया, इक्विटी ऐसी समय सीमा के महत्व को पार्टियों के मुख्य उद्देश्य के अधीन मानती

है, और यह विशिष्ट प्रदर्शन का आदेश देगी, भले ही न्यायालय के दृष्टिकोण से अनुबंध का अक्षरशः पालन नहीं किया गया हो।

ट्रायल कोर्ट ने अपने निष्कर्ष के समर्थन में तीन परिस्थितियों पर भरोसा किया कि समय बिक्री के अनुबंध का सार था:

i. हालांकि मौखिक समझौते द्वारा कोई समय निर्धारित नहीं किया गया था, 4 अप्रैल 1959 और 15 अप्रैल को लिखे गए समझौते में, 1959 में अनुबंध के निष्पादन के लिए तारीखें तय करने की निश्चित शर्तें थीं; (ii) दूसरे और तीसरे समझौते में ऐसे खंड शामिल थे जो डिफ़ॉल्ट के दोषी पक्ष पर जुर्माना लगाते थे; और

(iii) अपीलकर्ताओं 1 और 2 को पैसे की तत्काल आवश्यकता थी और अपनी तत्काल आवश्यकता को पूरा करने के लिए वे संपत्ति की बिक्री करना चाहते थे। लेकिन 4 अप्रैल और 15 अप्रैल के समझौते स्पष्ट भाषा में व्यक्त नहीं करते हैं कि समय का सार होना था और डिफ़ॉल्ट खंड का अस्तित्व जरूरी नहीं कि ऐसे इरादे का सबूत हो। उस अवधि का निर्धारण, जिसके भीतर अनुबंध निष्पादित किया जाना है, अनुबंध के सार के रूप में समय की शर्त नहीं लगाता है। यह सच है कि अपीलकर्ताओं 1 और 2 को पैसे की सख्त जरूरत थी, लेकिन उन्होंने प्रतिवादी से 3006/- रुपये प्राप्त कर लिए थे। और संभवतः कम से कम अस्थायी रूप से उनकी कठिनाइयों पर काबू पा लिया गया था। इस बात का कोई सबूत नहीं है कि जब

प्रतिवादी ने पूर्ण विचार आगे नहीं बढ़ाया तो उन्होंने अपनी तात्कालिक जरूरतों के लिए धन सुरक्षित करने के लिए अन्य व्यवस्थाएं कीं। समय को अनुबंध का सार बनाने का इरादा या तो स्पष्ट शर्तों से या उन परिस्थितियों से प्रमाणित हो सकता है जो सामान्य धारणा को विस्थापित करने के लिए पर्याप्त रूप से मजबूत हैं कि भूमि की बिक्री के अनुबंध में समय की शर्तें सार नहीं हैं। वर्तमान मामले में कोई स्पष्ट शर्त नहीं है, और परिस्थितियाँ ऐसी नहीं हैं जिससे यह संकेत मिले कि यह पार्टियों का इरादा था कि समय अनुबंध का सार था। यह सच है कि भले ही समय मूल रूप से महत्वपूर्ण नहीं था, अपीलकर्ता प्रतिवादी को दिए गए नोटिस द्वारा उसे निर्धारित समय के भीतर कन्वेयंस लेने के लिए कह सकते थे और सूचित कर सकते थे कि मांग के अनुपालन में चूक होने पर रद्द माना जाएगा। जैसा कि स्टिकनी बनाम कीबल में देखा गया है, जहां भूमि की बिक्री के लिए एक अनुबंध में पूरा होने के लिए निर्धारित समय अनुबंध का सार नहीं बनता है, लेकिन विक्रेता अनावश्यक देरी का दोषी है, क्रेता विक्रेता को एक समय सीमा सीमित करने वाला नोटिस जिसकी समाप्ति पर वह अनुबंध को समाप्त मान लेगा दे सकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ताओं 1 और 2 ने ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया है; 30 जुलाई, 1959 के अपने पत्र द्वारा उन्होंने अनुबंध को समाप्त मान लिया। यदि प्रतिवादी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री प्राप्त करने के लिए अन्यथा योग्य

था, तो उसका अधिकार अपीलकर्ताओं के पत्र 1 और 2 द्वारा निर्धारित नहीं किया जा सकता था।

लेकिन प्रतिवादी ने विशिष्ट निष्पादन के लिए एक डिक्री का दावा किया है और यह उसे स्थापित करना है कि वह अनुबंध की तारीख से अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए लगातार तैयार और इच्छुक था। यदि वह ऐसा करने में विफल रहता है, तो विशिष्ट पालना के लिए उसका दावा विफल हो जाना चाहिए। जैसा कि अर्देशिर मामा बनाम फ्लोरा सैसन (2) में प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समिति द्वारा देखा गया :

> "दूसरी ओर, विशिष्ट निष्पादन के लिए एक मुकदमे में, यह आवश्यक था और न्यायालय के द्वारा भी अनुबंध को विद्यमान मानने की अपेक्षा की गई। उस मुकदमे में उसे साबित करना आवश्यक था कि अनुबंध की तारीख से लेकर सुनवाई के समय तक, अपनी ओर से अनुबंध का पालन करने के लिए निरंतर तैयार और इच्छुक था। उस कथन को पूरा करने में विफलता के कारण उसके मुकदमा खारिज हो गया।"

किसी समझौते के विशिष्ट निष्पादन के मुकदमे में प्रतिवादी को यह दलील देनी होगी और साबित करना होगा कि वह अनुबंध की तारीख और मुकदमे की सुनवाई की तारीख के बीच लगातार अनुबंध के अपने हिस्से

को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। मामले के इस हिस्से पर ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी के खिलाफ स्पष्ट निष्कर्ष दर्ज किया कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए किसी भी समय तैयार और इच्छुक नहीं था। उच्च न्यायालय ने प्रतिवादी के दावे पर इस निष्कर्ष के प्रभाव पर विचार नहीं किया और उस निष्कर्ष पर असहमति व्यक्त किए बिना उसे विशिष्ट निष्पादन का आदेश दे दिया।

पक्षों की दलीलों, उठाए गए मुद्दों, ट्रायल कोर्ट द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों और प्रतिवादी के वकील द्वारा उच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर करने के आधार पर विचार करना आवश्यक है। वादपत्र के पैराग्राफों में प्रतिवादी ने कहा कि वह अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने और विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए हमेशा तैयार और इच्छुक था, लेकिन अपीलकर्ता 1 और 2 के अनुरोध पर विक्रय विलेख का निष्पादन स्थगित कर दिया गया था। अपीलकर्ताओं 1, 2 और 3 द्वारा इसका खंडन किया गया था। उन्होंने दलील दी कि प्रतिवादी बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था और वह जानबूझकर शेष राशि का भुगतान टाल रहा था और समझौते के निष्पादन में देरी कर रहा था।

यह भी दलील दी गई कि अपीलकर्ता 1 और 2 को "पैसे की बुरी तरह से जरूरत थी", लेकिन प्रतिवादी ने निर्धारित बिक्री को पूरा करने में

चूक की। ट्रायल जज ने दो मुद्दे उठाए जो मामले के इस हिस्से पर महत्वपूर्ण हैं

"2. क्या वादी अपने पक्ष में मुकदमे की संपत्तियों की बिक्री के विशिष्ट प्रदर्शन का हकदार नहीं है?

5. क्या अनुबंध का उल्लंघन प्रतिवादीगण (अपीलकर्ता 1 और 2) की गलती के कारण हुआ है या वादी (प्रतिवादी) की गलती के कारण?"

अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए प्रतिवादी की तत्परता और इच्छा के बारे में कोई विशेष मुद्दा नहीं उठाया गया था, लेकिन दूसरे मुद्दे में अपीलकर्ताओं, 1, 2 और 3 द्वारा उठाई गई याचिका का परीक्षण शामिल था। ऐसा प्रतीत होता है कि पार्टियां पूरी तरह से जागरूक थीं कि क्या साबित करना आवश्यक था, और इसी प्रकार अपने-अपने मामलों के समर्थन में सबूत पेश किए। बिना किसी विशिष्ट मुद्दे के उस याचिका की सुनवाई के विरोध में विचारण न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं उठाई गई।

मुकदमे में प्रतिवादी ने दावा किया कि 15 अप्रैल, 1959 को वह अपीलकर्ताओं 1 और 2 से विक्रय विलेख लेने को तैयार था, लेकिन 30 अप्रैल, 1959 को वह स्टाम्प पेपर खरीदने या विक्रय विलेख लेने के लिए तैयार नहीं था। कुछ हद तक असंगत रूप से उन्होंने कहा कि 30 अप्रैल, 1959

को वह अपीलकर्ताओं 1 और 2 से मिले और उन्हें बिक्री विलेख निष्पादित करने के लिए बुलाया और अपीलकर्ता 1 ने उन्हें बताया कि "उन्हें मामले में जाने की तत्काल आवश्यकता थी और उन्हें बाद में ही कब्ज़ा मिलेगा और उनके लौटने के बाद विक्रय पत्र निष्पादित किया जाएगा। "ट्रायल कोर्ट ने इस दलील पर विचार किया कि प्रतिवादी अनुबंध के अपने हिस्से को इस स्तर पर पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, उसी स्तर पर जैसे समय अनुंबंध का सार नहीं था। न्यायालय ने प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति का उल्लेख किया कि वह 30 अप्रैल, 1959 को बिक्री विलेख लेने को तैयार नहीं था, और फिर इस सवाल पर विचार किया कि क्या बिक्री 30 अप्रैल, 1959 तक प्रतिवादी या अपीलकर्ता 1 और 2 के डिफ़ॉल्ट के कारण पूरी नहीं हुई थी। सबूतों पर विचार करने पर, ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 तक बिक्री पूरी करने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह अपने वकील से परामर्श करने के लिए समय चाहता था। इस संदर्भ में कि प्रस्तावित विक्रय विलेख में अपीलकर्ता संख्या 1 के बच्चों का सत्यापन प्राप्त करने की वांछनीयता और अपीलकर्ता 1 और 2 ने स्थगन की मांग नहीं की। ट्रायल

कोर्ट ने तब इस बात पर विचार किया कि क्या डिफ़ॉल्ट प्रतिवादी द्वारा किया गया था या अपीलकर्ताओं 1 और 2 द्वारा, और पाया गया कि वादपत्र में केवल यह दावा करना कि वह अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था, पर्याप्त नहीं था और उसकी तत्परता और इच्छा होनी चाहिए। जो कि उसके आचरण से निर्णित किया जा सकता है। सबूतों की समीक्षा करने पर यह निष्कर्ष निकला कि प्रतिवादी ने 30 अप्रैल, 1959 को अनुबंध का पालन न करके और 30 अप्रैल के बाद भी अनुबंध का पालन न करके चूक की। वह अनुबंध पूरा करने के इच्छुक नहीं थे। विद्वान न्यायाधीश ने पाया कि मामले में कदम उठाने में देरी के लिए प्रतिवादी द्वारा निर्धारित वर्णित कारण "स्पष्ट रूप से असत्य" थे, और प्रतिवादी अपीलकर्ताओं पर दोष मढ़ने की कोशिश कर रहा था और बिक्री लेने में हुई चूक को समझाने के लिए बहाने खोज रहा था। उन्होंने अपने फैसले के पैराग्राफ-18 में निष्कर्ष निकाला: "मामले में सबूतों पर विचार करने से केवल एक ही बात का पता चलता है, अर्थात, वादी (प्रतिवादी) कभी भी बिक्री विलेख लेने के लिए उत्सुक, तत्पर या इच्छुक या इच्छुक नहीं था। [एक्स ए-2 और ए-3 में] यह वादी (प्रतिवादी) है जिसने

समझौते के अपने हिस्से के प्रदर्शन में चूक की है। "विद्वान न्यायाधीश ने तब कहा कि उनके विचार में समय अनुबंध का सार था और भले ही ऐसा नहीं था, तब भी अनुबंध दिनांक 4 अप्रैल, 1959 के समझौते और अप्रैल के समझौते में तय की गई तारीख के बाद उचित समय के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए और ऐसा नहीं किया गया। इसके बाद ट्रायल कोर्ट ने प्रतिवादी और अपीलकर्ताओं 1 और 2 के आचरण के बारे में सबूतों का सारांश दिया और माना कि प्रतिवादी "किसी भी समय अपने हिस्से या अनुबंध को पूरा करने के लिए कभी भी तैयार और इच्छुक नहीं था।"

ट्रायल जज ने स्पष्ट रूप से दो स्वतंत्र मुद्दों को उलझा दिया, एक प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के निष्पादन में चूक का और दूसरा अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए प्रतिवादी की तत्परता और इच्छा का। जैसा कि पहले देखा गया है, यदि समय अनुबंध का सार नहीं है, तो डिफ़ॉल्ट तब होता है जब एक पक्ष समय का सार बनाते हुए नोटिस देता है और अनुबंध की शर्तों को पूरा करने के लिए नोटिस द्वारा निर्धारित उचित समय के भीतर दूसरे पक्ष की आवश्यकता होती है, और जिस पक्ष को नोटिस दिया गया वह मांग का अनुपालन करने में विफल रहता है। इस मामले में

ऐसा कोई नोटिस नहीं दिया गया था, और अपीलकर्ताओं 1 और 2 को अनुबंध पूरा करने के लिए बुलाने में हुई देरी से, प्रतिवादी की ओर से डिफ़ॉल्ट का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट इस निष्कर्ष पर भी पहुंचा कि प्रतिवादी का आचरण, जैसा कि उसके बयान और उसके गवाहों से पता चलता है, यह साबित करता है कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। न्यायालय ने यह अनुमान 30 अप्रैल, 1959 के बाद तीन महीने की देरी और प्रतिवादी द्वारा उस देरी और अन्य परिस्थितियों को समझाने के लिए दिए गए सबूतों से लगाया।

ट्रायल कोर्ट ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के दावे के प्रतिकूल मुद्दे संख्या 2 पर एक निष्कर्ष दर्ज किया। प्रतिवादी ने, जैसा कि पहले ही देखा जा चुका है, दावा किया था कि वह अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था और अपीलकर्ताओं 1, 2 और 3 ने उस दावे को अस्वीकार कर दिया था। इससे पहले कि उसे विशिष्ट पालना के लिए डिक्री दी जा सके, प्रतिवादी को अनुबंध की तारीख से मुकदमे की सुनवाई की तारीख तक लगातार अपनी तत्परता और इच्छा साबित करनी थी और यदि वह इसमें विफल रहता था, तो उसका मुकदमा विफल हो जाता था। और ट्रायल कोर्ट ने उस आधार पर प्रतिवादी के मुकदमे को भी खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय अपीलकर्ताओं 1 और 2 के खिलाफ प्रतिवादी के पक्ष

में विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री तभी दे सकता है जब न्यायालय संतुष्ट हो कि प्रतिवादी मुकदमे की तारीख से अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए लगातार तैयार और इच्छुक था। लेकिन उच्च न्यायालय में प्रतिवादी ने स्पष्ट रूप से प्रतिवादी के खिलाफ उस प्रश्न पर ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष को चुनौती नहीं दी।m उन्होंने उच्च न्यायालय को केवल इस आधार पर अपील पर निर्णय लेने के लिए आमंत्रित किया कि भले ही प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 को या उस तारीख से पहले प्रतिवादी बिक्री के लिए आवश्यक धन के साथ तैयार नहीं था" वह फिर भी विशिष्ट निष्पादन के लिए डिक्री का हकदार था। इस प्रकार दर्ज किया गया बयान कुछ हद तक अस्पष्ट है: विशिष्ट पालना के लिए प्रतिवादी के दावे को खारिज करने का आधार केवल इसलिए उत्पन्न नहीं होगा क्योंकि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 को आवश्यक धन के साथ तैयार नहीं था, यदि समय सार नहीं था। लेकिन यदि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 को अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, तो उसका मुकदमा विफल हो जाना चाहिए।

ट्रायल कोर्ट ने पाया कि प्रतिवादी ने अनुबंध के अपने हिस्से का पालन करने में चूक की है। अदालत ने यह अनुमान अदालत के समक्ष दिए गए उनके बयान और सबूतों से लगाया कि निष्पादन के लिए निर्धारित तिथि के तीन महीने बाद तक प्रतिवादी द्वारा अनुबंध को पूरा

करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया गया था। हालाँकि, यह निष्कर्ष आवश्यक रूप से अपीलकर्ताओं 1 और 2 को अनुबंध निष्पादित करने के लिए बुलाने में देरी से नहीं निकलता है। लेकिन ट्रायल कोर्ट ने यह भी पाया कि प्रतिवादी किसी भी समय अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। इस निष्कर्ष को कभी भी उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती नहीं दी गई और उच्च न्यायालय ने यह नहीं माना कि यह निष्कर्ष गलत था। प्रतिवादी के वकील ने आग्रह किया कि तत्परता और इच्छा के मुद्दे पर ट्रायल कोर्ट का निष्कर्ष "बिना सबूत, अस्पष्ट और विकृत" था और उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों द्वारा इसे "पूरी तरह से अनदेखा" करना और डिक्री देना उचित था। इस निष्कर्ष को अजीब या बिना सबूत के नहीं ठहराया जा सकता है। ट्रायल जज ने सबूतों के बारे में अपने दृष्टिकोण से माना कि प्रतिवादी किसी भी समय अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। क्या साक्ष्य उस निष्कर्ष को उचित ठहराते हैं, यह एक ऐसा मामला है जिस पर हम फिलहाल विचार स्थगित कर सकते हैं। लेकिन यह उन आधारों में से एक है जिस पर मुकदमा ट्रायल कोर्ट द्वारा खारिज कर दिया गया था। सबूतों पर विचार किए बिना और उस निष्कर्ष को रद्द किए बिना, विशिष्ट पालना के लिए डिक्री नहीं दी जा सकती है, और उच्च न्यायालय के फैसले में मामले के इस हिस्से पर सबूतों की कोई चर्चा नहीं है।

प्रतिवादी के वकील ने तब आग्रह किया कि दूसरे मुद्दे पर ट्रायल जज द्वारा उठाया गया निष्कर्ष, जहां तक यह प्रतिवादी द्वारा अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने की तत्परता और इच्छा से संबंधित है, उसके द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों पर नहीं उठाया जा सकता है। प्रतिवादी ने कहा था कि वह 30 अप्रैल, 1959 को स्टाम्प-पेपर खरीदने या विक्रय विलेख लेने के लिए तैयार नहीं था। 30 अप्रैल, 1959 के बाद भी ट्रायल जज के अनुसार प्रतिवादी ने अपीलकर्ताओं 1 और 2 को अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए बुलाने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, और स्टाम्प पेपर नहीं खरीदा। ट्रायल जज ने यह भी पाया कि प्रतिवादी की कहानी में अपीलकर्ता नंबर 1 ने अनुरोध किया था कि बिक्री के पूरा होने को स्थगित कर दिया जाए क्योंकि उसे मदुरै में एक सामाजिक समारोह में भाग लेना था और उसके बाद उसे अपनी पोती के लिए उपयुक्त मैच के लिए पूछताछ करनी थी और जुलाई 1959 के पहले सप्ताह में अपीलकर्ता नंबर 1 और प्रतिवादी ड्राफ्ट सेल-डीड की तैयारी के लिए वी. पिल्लई पीडब्लू 3 के पास गए और पहले अपीलकर्ता ने अपने बेटे और बेटियां का सत्यापन प्राप्त करने के लिए समय मांगा जो कि, सच नहीं था, और प्रतिवादी अपीलकर्ताओं 1 और 2 पर देरी के लिए दोष मढ़ने का प्रयास कर रहा था और विक्रय-पत्र लेने के लिए अपनी अनिच्छा को दूर करने के लिए बहाने बनाने की कोशिश कर रहा था। ट्रायल कोर्ट के विचार में प्रतिवादी इस बात को लेकर अनिर्णीत था कि उसे अनुबंध पर अमल करना चाहिए या नहीं,

और वह स्पष्ट रूप से मामले को आगे बढ़ने देने के लिए तैयार था। इसलिए, ट्रायल कोर्ट प्रतिवादी द्वारा की गई स्वीकारोक्ति, उसके बाद के आचरण और अन्य परिस्थितियों के संबंध में इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि प्रतिवादी तैयार नहीं था, और किसी भी समय विक्रय पत्र लेने को तैयार नहीं था। यह निष्कर्ष प्रथम दृष्टया अच्छे सबूतों पर आधारित है, और ट्रायल कोर्ट द्वारा दिया गया निष्कर्ष उचित है। इस न्यायालय के लिए सबूतों के पुनर्मूल्यांकन के बिना निष्कर्ष को रद्द करना मुश्किल होगा। अपीलकर्ता के वकील ने हमसे नहीं कहा है - और हमें लगता है कि उन परिस्थितियों में वह ऐसा करने में सही था - रिकॉर्ड पर साक्ष्य की समीक्षा करने और साक्ष्य पर प्रतिवादी की तत्परता और इच्छा की दलील पर एक स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए , जैसा कि उच्च न्यायालय के विद्वान न्यायाधीशों ने किया होगा यदि प्रश्न उनके समक्ष उठाया गया था। ट्रायल कोर्ट का यह निष्कर्ष कि अनुबंध करने के बाद प्रतिवादी अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था, को स्वीकार किया जाना चाहिए। अपील स्वीकार की जाती है और उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त किया जाता है, और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को बहाल कर दिया जाता है। इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में कॉस्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं होगा।

बाचावत, जमशेद बनाम बुर्जोरजी के फैसले को ध्यान में रखते हुए, उच्च न्यायालय ने सही माना कि समय अनुबंध का सार नहीं था। अनुबंध 5 मार्च, 1959 को दर्ज किया गया था। उस दिन, प्रतिवादी ने 1,006/- रुपये की राशि का भुगतान किया। 4 अप्रैल, 1959 को, दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए कि बिक्री 15 अप्रैल, 1959 से पहले पूरी हो जानी चाहिए। उस दिन, प्रतिवादी ने रुपये की एक और राशि 2,000/- जमा की। 15 अप्रैल 1959 को बिक्री पूरी करने का समय 30 अप्रैल 1959 तक बढ़ा दिया गया। लेन-देन 30 अप्रैल, 1959 के भीतर पूरा नहीं हुआ था। लेकिन चूंकि समय अनुबंधका सार नहीं था, इसलिए अनुबंध जीवित रहा। 30 जुलाई 1959 को, अपीलकर्ताओं ने अनुबंध को अचानक रद्द कर दिया।

राशि जब्त कर ली। प्रतिवादी ने रद्दीकरण स्वीकार नहीं किया। 3 अगस्त, 1959 को उन्होंने शेष मूल्य 13,906/- रुपये जमा कर दिये। 4 अगस्त, 1959 को, उन्होंने अपीलकर्ताओं को समझौते का पालन करने के लिए बुलाया। 21 मार्च, 1960 को, प्रतिवादी ने वर्तमान मुकदमा दायर किया। उच्च न्यायालय ने इस तर्क को खारिज कर दिया कि विशिष्ट पालना की राहत विलंब के कारण नहीं दी गई। अपीलकर्ता अब यह आग्रह नहीं करते कि प्रतिवादी देरी के आधार पर राहत का हकदार नहीं था। अपीलकर्ताओं के वकील ने नया मुद्दा उठाया कि प्रतिवादी विलंब के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था और इस आधार

पर उसका मुकदमा खारिज कर दिया जाना चाहिए। मुझे उच्च न्यायालय के निर्णय में इस तर्क का कोई अंश नहीं मिला। उच्च न्यायालय के समक्ष, वर्तमान अपीलकर्ताओं ने केवल दो बिंदुओं पर आग्रह किया, अर्थात, (ए) समय अनुबंध का सार था और इसलिए प्रतिवादी अनुबंध के उल्लंघन का दोषी था और (बी) किसी भी घटना में, प्रतिवादी विलंब के आधार पर राहत का हकदार नहीं था। हाई कोर्ट ने इन दोनों दलीलों को खारिज कर दिया। अपीलकर्ताओं ने ट्रायल कोर्ट के इस निष्कर्ष नहीं माना कि प्रतिवादी अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। यदि अपीलकर्ताओं ने इस निष्कर्ष को माना होता, तो उच्च न्यायालय ने इसका उचित निपटारा किया होता। उच्च न्यायालय यह पाए बिना कि प्रतिवादी हर समय अनुबंध का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक था, विशिष्ट पालना के लिए मुकदमे का फैसला नहीं दे सकता था।

ट्रायल कोर्ट ने छह मुद्दे तय किए। इस प्रश्न पर कोई विशेष मुद्दा नहीं था कि क्या प्रतिवादी अनुबंध निष्पादित करने के लिए तैयार और इच्छुक था। मैं किसी भी न्यायालय का विरोध करता हूं, चाहे वह मुफस्सिल न्यायालय हो या उच्च न्यायालय, जो इस मुद्दे पर कोई विशेष मुद्दा उठाए बिना ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर निष्कर्ष दर्ज कर रहा है। अंक क्रमांक 2 एक सामान्य मुद्दा था. मुद्दा यह था कि "क्या वादी अपने पक्ष में मुकदमे की संपत्तियों की बिक्री के विशिष्ट प्रदर्शन का हकदार नहीं है।"इस मुद्दे के तहत,

ट्रायल कोर्ट ने अपने फैसले के पैराग्राफ 17 से 20 में, तत्परता और इच्छा, अनुबंध के प्रदर्शन में डिफ़ॉल्ट, देरी, वेवर और परित्याग जैसे सभी प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा की। ट्रायल कोर्ट के निष्कर्ष का सार यह था कि समय अनुबंध का सार था, और चूंकि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 तक अपना अनुबंध पूरा करने में विफल रहा था, वह अनुबंध के उल्लंघन का दोषी था और विशिष्ट पालना का दावा नहीं कर सकता था। आगे कहा कि प्रतिवादी देरी, छूट और परित्याग के आधार पर राहत का हकदार नहीं था। संयोग से, चूँकि प्रतिवादी 30 अप्रैल, 1959 तक अनुबंध को पूरा करने में विफल रहा था और 30 जुलाई, 1959 तक कोई कदम नहीं उठाया था, ट्रायल कोर्ट ने पाया कि वह अनुबंध को पूरा करने के लिए कभी भी तैयार और इच्छुक नहीं था। तत्परता के संबंध में निष्कर्ष इस निष्कर्ष से जुड़ा था कि समय अनुबंध का सार था और प्रतिवादी देरी के आधार पर किसी राहत का दावा नहीं कर सकता था। जैसा कि हम इस निष्कर्ष को अपास्त रहे हैं कि समय अनुबंध का सार था और यह भी कि देरी के आधार पर प्रतिवादी राहत पाने का हकदार नहीं था, हमें इस निष्कर्ष को अपास्त देना चाहिए कि प्रतिवादी अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था।

अपीलकर्ताओं के वकील ने प्रतिवादी द्वारा अपनी जिरह में की गई स्वीकारोक्ति पर जोर दिया कि 30 अप्रैल, 1959 को वह स्टाम्प पेपर खरीदने या विक्रय विलेख लेने के लिए तैयार नहीं था। वकील ने प्रतिवादी

की ओर से दी गई रियायतों पर भी भरोसा किया और उच्च न्यायालय के फैसले में निम्नलिखित अंशों में दर्ज किया गया।

> "हमारे सामने अपीलकर्ता के लिए श्री केएस देसिकन ने इस निष्कर्ष को जाहिर करने का कोई प्रयास नहीं किया कि उनका मुवक्किल ने 30 अप्रैल, 1959 को, या उस तारीख से पहले अपीलकर्ता बिक्री के लिए आवश्यक धनराशि के साथ तैयार नहीं था..... तो सवाल यह है कि क्या अपीलकर्ता, जैसा कि ट्रायल कोर्ट ने पाया था, जो, हमारे सामने कोई विवाद नहीं है, एक डिफ़ॉल्ट पार्टी है, वह विशिष्ट पालना के लिए डिक्री का हकदार है। यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या अपीलकर्ता की ओर से अनुचित देरी हुई थी और क्या उत्तरदाताओं 1 और 2 ने उसे उचित नोटिस दिया है कि उसे एक निश्चित समय के भीतर समझौते को पूरा करना होगा।"

इन स्वीकारोक्ति का प्रभाव यह है: यदि समय अनुबंध का सार था, तो प्रतिवादी ने 30 अप्रैल, 1959 को चूक कर दी थी। लेकिन यदि समय अनुबंध का सार का नहीं था, तो उसने अनुबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया था और तब एकमात्र सवाल यह था कि क्या देरी के आधार पर उन्हें विशिष्ट पालना से राहत देने से इनकार किया जा सकता है। अब यह तर्क

नहीं दिया गया है कि प्रतिवादी देरी के आधार पर राहत पाने का हकदार नहीं है। चूंकि समय अनुबंध का सार नहीं था, इसलिए यह अपीलकर्ताओं का कर्तव्य था कि वे बिक्री के पूरा होने के लिए उचित समय तय करते हुए प्रतिवादी को एक नोटिस दें। उन्होंने ऐसा नहीं किया। बिक्री पूरी करने के लिए उचित समय तय करने के बजाय, उन्होंने 31 जुलाई, 1959 को अपने पत्र द्वारा अनुबंध को गलत तरीके से रद्द कर दिया। बिक्री पूरी करने में प्रतिवादी की ओर से निस्संदेह देरी हुई थी। प्रतिवादी के अनुसार, अपीलकर्ता विभिन्न बहानों से बिक्री को टाल रहे थे, लेकिन इस बिंदु पर उनकी गवाही को ट्रायल कोर्ट ने स्वीकार नहीं किया। इससे पता चलता है कि बिक्री पूरी होने में देरी के लिए कोई स्पष्टीकरण नहीं था। लेकिन उच्च न्यायालय ने सही पाया कि न तो देरी और न ही देरी की व्याख्या करने में विफलता राहत से इनकार करने का आधार है।

सबूतों पर चर्चा करने के बाद, ट्रायल कोर्ट ने निम्नलिखित निष्कर्ष दर्ज किया:

> "वादी की ओर से मामले में कोई भी कदम उठाने में देरी या चूक के कारण स्पष्ट रूप से असत्य हैं, और यह स्पष्ट है कि वह प्रतिवादी पर दोष मढ़ रहा था और स्पष्टीकरण के लिए कोई न कोई कारण ढूंढ रहा था। इस प्रकार 30-4-1959 से जुलाई 1959 के मध्य तक, वादी ने मामले में

कोई कदम नहीं उठाया... समय 30-4-1959 तक समाप्त हो गया। वादी द्वारा 3 महीने की अवधि के लिए 30-7-1959 तक कुछ भी नहीं किया गया था। वादी ने 3 महीने की उक्त अवधि के लिए समझौते को निष्पादित करने के लिए अपनी ओर से कुछ भी नहीं किया।"

इस निष्कर्ष के आधार पर यह माना गया कि प्रतिवादी अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था। यह कहा :

"मामले में सबूतों पर विचार करने से केवल एक ही बात का पता चलता है, यानी कि वादी कभी भी एक्स-ए-2 और ए-3 के अनुसरण में बिक्री विलेख लेने के लिए उत्सुक, त्वरित या इच्छुक या इच्छुक नहीं था। यह वादी है जिसने समझौते के अपने हिस्से के निष्पादन में चूक की... भले ही समय अनुबंध का सार नहीं था, वादी किसी भी समय अनुबंध के अपने हिस्से को पूरा करने के लिए तैयार या इच्छुक नहीं था।"

मेरी राय है कि ट्रायल कोर्ट यह निष्कर्ष निकालने में स्पष्ट रूप से गलत था कि प्रतिवादी इस तथ्य से अनुबंध का पालन करने के लिए तैयार और इच्छुक नहीं था कि 30 अप्रैल, 1959 से जुलाई 1959 के मध्य तक प्रतिवादी ने कोई कदम नहीं उठाया था। यदि प्रतिवादी विलंब का दोषी था,

तो बिक्री के पूरा होने के लिए उचित समय तय करना अपीलकर्ताओं का कर्तव्य था। केवल देरी, वेवर में कमी या अनुबंध का परित्याग राहत से इनकार करने का कोई आधार नहीं है, न ही यह तत्परता और इच्छा की कमी का सबूत है। रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्री स्पष्ट रूप से इंगित करती है कि प्रतिवादी हर समय अनुबंध को पूरा करने के लिए तैयार और इच्छुक था। कुल प्रतिफल राशि रु.15,106/- थी। 5 मार्च 1959 को, प्रतिवादी ने 1,006/- रुपये की अग्रिम जमा राशि जमा की। 4 अप्रैल, 1959 को, उन्होंने 2,000/- रुपये की एक और राशि जमा की। 30 जुलाई, 1959 का पत्र मिलते ही उन्होंने एक बैंक में 13,906/- रु. शेष राशि रुपये जमा कर दिये। वकील ने आग्रह किया कि 30 जुलाई, 1959 से पहले प्रतिवादी को पैसे के साथ तैयार रहना चाहिए था। इस तर्क में कोई बल नहीं है. बैंक ऑफ इंडिया लिमिटेड बनाम जमशेदजी एएच चिनॉय और मेसर्स चिनॉय एंड कंपनी में, प्रिवी काउंसिल ने शेयर बेचने के अनुबंध के विशिष्ट पालना का आदेश दिया। अनुबंध को पूरा करने के लिए खरीदार की तत्परता और इच्छा के सवाल पर, लॉर्ड मैकडरमॉट ने पृष्ठ 91 पर कहा।

> "यह सच है कि पहले वादी ने कहा था कि वह अपने लिए खरीद रहा था, कि उसके पास कीमत को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन तैयार नहीं था और रद्द करने के समय इसे प्राप्त करने के लिए कोई निश्चित व्यवस्था नहीं की गई थी।

लेकिन खुद को तैयार और इच्छुक साबित करने के लिए खरीदार को पैसे को प्रस्तुत करने या लेनदेन के किसी व्यवहार या योजना की पुष्टि करने के लिए आवश्यकता नहीं है।

मेरी राय में, प्रतिवादी अनुबंध के विशिष्ट पालना का हकदार है, और उच्च न्यायालय ने मुकदमे पर सही फैसला सुनाया। परिणामस्वरूप, अपील कास्ट सहित खारिज की जाती है।"

आदेश

बहुमत की राय के अनुसार अपील स्वीकार की जाती है, उच्च न्यायालय द्वारा पारित डिक्री को अपास्त कर दिया जाता है और ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित डिक्री को रिस्टोर कर दिया जाता है। इस न्यायालय और उच्च न्यायालय में कास्ट के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।
आरकेपीए

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी पायल अग्रवाल (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरणः यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिये स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिये इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिये निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।